

प्रेषक,

आर.सी. अग्रवाल,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अधिशाली अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
दुगड़ा / बागेश्वर,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून:: दिनांक: 26 : सितम्बर, 2011

विषय:- द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार विगत वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु नगरपालिका परिषदों को चतुर्थ त्रैमासिक किश्त की अवशेष धनराशि का वित्तीय वर्ष 2011-12 में संकमण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-47/XXVII(1)/2009 दिनांक 20 जनवरी, 2009 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा उक्त शासनादेश के संलग्नानुसार समस्त नगर पालिका परिषदों को राज्य की वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008-09 की चतुर्थ तिमाही (जनवरी से मार्च) हेतु **रु0 67564154 (रु0 छः करोड़ पचहत्तर लाख चौसठ हजार एक सौ चवन मात्र)** हेतु अवमुक्त की गई थी। 12वाँ वित्त आयोग की संस्तुतियों पर नगर पालिका परिषदों को वित्तीय वर्ष 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 में अवमुक्त धनराशि उपयोगिता प्रमाण-पत्र ना मिलने के कारण उनको देय समनुदेशन से समायोजित किया गया था।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 12वाँ वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत निकायों को अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाने के कारण रोकी गई धनराशि **रु0 1402253.00 (रु0 चौदह लाख दो हजार दो सौ तिरेप्पन मात्र)** संलग्न विवरण के अनुसार अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- अवमुक्त की जा रही धनराशि शासनादेश सं0-47/XXVII(1)/2009 दिनांक 20 जनवरी, 2009 में उल्लिखित शर्तों के अधीन ही व्यय की जायेगी।


4- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्यय की अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-आयोजनेत्तर-01-नगरीय स्थानीय

म

निकाय-192-नगरपालिका/नगर निकाय-03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन-00-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,



(आर.सी. अग्रवाल)
अपर सचिव, वित्त।

संख्या:- 564 (1)/XXVII(1)/2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ, उत्तराखण्ड।
- 4- निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, माता मन्दिर रोड, देहरादून।
- 5- जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर, उत्तराखण्ड।
- 6- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
- 7- मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल/ बागेश्वर, उत्तराखण्ड।
- 8- विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो।
- 9- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
- 10- एन० आई०सी०, सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,


(आर.सी. अग्रवाल)
अपर सचिव, वित्त।


शासनादेश संख्या: 564 /XXVII (i) /2011

दिनांक: 26 : सितम्बर, 2011 का संलग्नक।

द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु नगर पालिका परिषदों को चतुर्थ त्रैमास से रोकी गई धनराशि का संकमण।

क0सं0	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	राज्य वित्त आयोग की संस्तुति पर वर्ष 2008-09 हेतु चतुर्थ किश्त हेतु देय संकमण	अवमुक्त धनराशि	(धनराशि रू0 में) उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त जारी की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1-नगर पालिका परिषद				
1- दुगड्डा		197000	0	197000
2- बागेश्वर		2050000	844747.000	1205253
योग		2247000.00	844747.00	1402253.00

(रू0 चौदह लाख दो हजार दो सौ तिरेप्पन मात्र)


(आर.सी. अग्रवाल)
अपर सचिव, वित्त।